that people should not drink but the question is whether the prohibition policy as followed has led to that result or not. This is our concern. That is why in the earlier period we had thought that we should lay stress on temperance rather than prohibition as such. As I have already said—this is my personal view and not necessarily government's—so far as a rich person is concerned, if he wants to drink and does not mind dying of drink, it is his business but when an industrial labourer or a poor man because of addiction to drink deprives his family of food and other essential commodities, then it does become the business of society and of government. Somehow we have to work out a policy. So far, I am sorry to say, the prohibition policy has not worked in any place, not even in Gujarat where so much effort was made to this end.

SHRI RATANSINH RAJDA: I am thankful to the Prime Minister but I want to say that the gentleman who gave the advertisement happens to be the President of the local Congress (I).

SHRIMATI INDIRA GANDHI: I did not know about it. We shall look into it.

ग्रामीण विद्युतीकरण

*759. **श्री राम विलास पासवान** : क्या योजना मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में कोई मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त मूल्यांकन करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई और किन-किन गावों के बारे में उक्त मूल्यांकन किया गया तथा यह मूल्यांकन किस अवधि में किया गया ;

(ग) क्या उसके अन्तरिम निष्कर्षों की कोई रिपोर्ट प्रकाशित की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ). योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने "ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का मूल्यांकन" अध्ययन किया है । राज्यों को स्तर मानते हुए बहु-चरणीय स्तरबद्ध नमूना-चयन की प्रक्रिया अपनाई गई है, इसमें जिले नमूना-चयन की प्राथमिक इकाई हैं, राज्य बिजली बोर्डों के अनुभाग कार्यालय/सबडिवीजन, पोषक लाइनें, गांव और लाभग्राही परिवार नमूना-चयन की बाद की इकाइयां हैं । 19 राज्यों के 48 जिलों में अवस्थित 397 नमूना गावों के नामों की सूची सभा पटल पर प्रस्तुत हैं । [**ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये** संख्या LT--1187/80] इस अध्ययन का क्षेत्रीय कार्य जनवरी, 1979 में शुरू किया गया था और सितम्बर, 1979 के अन्त तक पूरा हुआ था । अंतरिम निष्कर्षों की किसी रिपोर्ट को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है या प्रकाशित नहीं किया गया है ।

श्री राम विलास पासवान : एक तरफ कुछ राज्य ऐसे है जहां सैट परसैंट गावों में बिजली उपलब्ध है, दूसरी तरफ बिहार, यू0 पी0, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्य हैं जहां मुश्किल से 25 से 32 परसैंट तक गावों में विद्युतीकरण हुआ है। यह जो क्षेत्रीय असन्तुलन है इसको मिटाने के लिए आप क्या कर रहे हैं ? आपने क्या कोई सैम्पल सर्वे कराया है कि कितने किसानों को समय पर बिजली नहीं मिलने के कारण कितनी क्षति उठानी पड़ती है और विगत जनवरी से जून 1980 तक प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में कितने घंटे तक बिजली रही है? क्या सरकार फसल तैयार होने के समय अगर बिजली नहीं मिलती है और उस कारण से फसल की बरबादी होती है तो किसान को कम्पैसेट करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : विद्वान सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि यह मूल्यांकन का प्रश्न नीति निर्धारण से भिन्न होता है । मूल्यांकन, जो पहले से कार्यक्रम चल रहे हैं उनका दूरगामी तथा तात्कालिक क्या प्रभाव पड़ा है, उसका होता है । इसलिए जो प्रश्न विद्वान सदस्य ने पूछा है वह मूल्यांकन से संबंधित नहीं है । जहां तक क्षेत्रीय असंतुलन का संबंध है छठी योजना का जो विद्युत प्रक्रिया वर्ग है, वर्किंग ग्रुप है वह उस संबंध में अपनी संस्तुति देगा कि ग्रामीण विद्युतीकरण के मामले में जो असन्तुलन है उसको किस प्रकार दूर किया जा सकता है ।

जहां तक उनका दूसरा प्रश्न है कि गांवों में समय से बिजली पहुंची या नहीं, यह प्रश्न भी मूल्यांकन की जो प्रश्न सारणी है उसमें पूछा गया है । ग्रामीण जीवन में बिजली समय से न मिलने के कारण उसका क्या प्रभाव पड़ा है ये सब प्रश्न प्रश्न सारिणी में उपलब्ध हैं । उनके उत्तरों का इस समय विश्लेषण किया जा रहा है, एनेलेसिस किया जा रहा है और जब उसकी अंतरिम रिपोर्ट आएगी तो इसका मूल्यांकन भी हमें प्राप्त हो जाएगा ।

श्री राम विलास पासवान : मेरा सीधा सा प्रश्न हिन्दी में था । अंग्रेजी में प्रश्न इस प्रकार है :

Whether Planning Commision has made an assessment in regard to rural electrification...

पता नहीं आपने कैसे उसको मूल्यांकन के नाम पर काट दिया है । सीधा सा जो प्रश्न पूछा गया है वह यह है कि बिजली नहीं मिलने के कारण गावों में जो तबाही होती है और वहां जहां इलैक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, किसान का खेत सूख जाता है, उसकी पैदावार मारी जाती है, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं ?

दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि कुल जितने गांव देश में है उनमें से शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के कितने गांव हैं, उनमें से कितने गावों का आपने विद्युतीकरण कर दिया है? और जिनका नहीं किया है उसका क्या कारण है? क्या सरकार विद्युतीकरण के साथ-साथ उसके और जिनका नहीं किया है उसका क्या कारण मुताबिक क्षमता भी उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है, कोई प्रयास कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : अगर आप इस सवाल को एनर्जी मिनिस्टर से करते तब आप को इसका उत्तर मिल सकता था कि बिजली क्यों नहीं मिल रही है ?

श्री राम विलास पासवान कितने गांवों में विद्युतीकरण की आपकी योजना है और कितने गांवों का अभी तक विद्युतीकरण हो गया है ?

अध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न इसके बारे में एनर्जी मिनिस्टर से पूछ लें तो ज्यादा बेहतर होगा।

श्री राम विलास पासवान : कितने गावों में बिजली देने की योजना है और कितने गांवों में लग चुकी है, यह भी बताना क्या इनके लिए मुश्किल है ?

अध्यक्ष महोदय : आपके पास तो यह इन-फर्मेशन नहीं होगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : इसके बारे में यदि विद्वान सदस्य दूसरा प्रश्न पूछ लें तो ज्यादा अच्छा होगा । इसका मूल्यांकन से कोई सीधा संबंध नहीं है ।

MR. SPEAKER: How many villages are you going to electrify?

श्री नारायण दत्त तिवारी : इसके लिए छठी योजना में प्रावधान किया जायेगा । वह अभी बन रही है ।

श्री राम विलास पासवान : यह तो स्पष्ट ही है कि छठी योजना में किया जायेगा, चाहे दस गांवों में करें या बीस गांवों में करें । मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने गांवों के विद्युतीकरण की योजना है और उनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के कितने गांव इनक्लूड किये जायेंगे ।

MR. SPEAKER: I don't think he will be having that information now because the Plan is being finalised.

प्रो० मधु दण्डवते : ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण के कार्यक्रम के लिए स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्ज की मदद ली जाती है । आज स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्ज जिस तरह से काम कर रहे है और उन्हें जो घाटा हो रहा है, उसे देखते हुए क्या सरकार के पास ऐसी परियोजना है कि स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्डज को केन्द्र अपने हाथ में ले ले, या उसके विकल्प में क्या सरकार यह तय करेगी कि एक नेशनल ग्रिड का निर्माण किया जाये ?

SHRI K. LAKKAPPA: This question does not pertain to Planning Department. How can he ask this question from the Minister of Planning?

MR. SPEAKER: This could be a question of planning. He wants to know whether he intends to do it or not.

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन् विद्वान सदस्य के पहले प्रश्न के उत्तर में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान संवैधानिक स्थिति में यह संभव नहीं होगा कि राज्य विद्युत बोर्डों को केन्द्र अपने हाथ में ले ले । उन पर नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है, इस पर माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने इस सदन का समाधान किया है । जहां तक नेशनल ग्रिड बनाने का प्रश्न है, यह एक ऐसा प्रश्न है, जिसका विचार किया जा रहा है और हम इसको प्राथमिकता देने का प्रयास करेंगे कि नेशनल ग्रिड का निर्माण किया जाये ।

श्री एम० सत्यनारायण राव : माननीय सदस्य, श्री पासवान, ने प्रश्न पूछा है कि इलैक्ट्रिफाइड गावों का परसेंटेज क्या है । मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं लेकिन आपको मालूम है कि आजादी के समय हिन्दुस्तान में सिर्फ 1500 गांवों में इलैक्ट्रिसिटी थी । अब वैसी स्थिति नहीं है । लाखों गांवों का इलैक्ट्रिफिकेशन हो चुका है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सवाल पूछें ।

SHRI M. SATYANARAYAN RAO: Only 45 per cent of the villages have been covered by the electrification scheme. I would like to know from the Minister whether in Sixth Plan at least cent per cent villages will be electrified. Recently I put a question to the Energy Minister. He said that it did not come under his Ministry. The Power Minister said that he had no financial powers. I would like to know whether the Planning Minister will be able to give this information.

SHRI N. D. TIWARI: His question first of all has to be answered by the State Governments. They have to provide for rural electrification outlays in their State Plans. So, in different States we have different view of the matter and in some States we have achieved cent per cent electrification, in some States we have achieved 60 to 70 per cent and in some other States we have achieved 30 to 40 per cent electrification. So, primarily it is the responsibility of the State Government to formulate the plan. We would very much like to give them high priority.

श्री भागवत झा आजाद : ग्रामीण विद्युतीकरण से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या विद्युत् तापघर को पिटहैड पर बनाया जाये, जहां कम से कम खर्च हो, या वहां बनाया जाये, जहां कोयला सौ मील दूर ले जाना पड़े और खर्च अधिक से अधिक हो । मैं यह जानना चाहता हूं कि विद्वान योजना मंत्री जी इनमें से किसको अधिक उपयुक्त समझते हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : हमारे परम विद्वान सदस्य ने जो विचार व्यक्त किया है कि कम कीमत के पिट हैड्ज पर थर्मल स्टेशन बनाये जायें, यह बहुत स्तुत्य है और स्वागतयोग्य है और ऊर्जा मंत्री जी ने इस सम्बंन्ध में जो नीति घोषित की है, उसमें यही कहा है कि भविष्य में प्राथमिकता पिट हैड थर्मल्स को ही दी जायेगी, लेकिन जो दूरगामी राज्य हैं जहां पर कि ऊर्जा कोले जाने में बहुत खर्चा करना पड़ता है और वहां की क्षेत्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए कहीं-कहीं पर यह हो सकता है कि उनको भी थर्मल स्टेशन बनाने की इजाजत दी जाये, लेकिन जहां तक प्राथमिकता का सवाल है कि यह पिट हैड थर्मल स्टेशन्ज को ही दी जानी चाहिए, यह नीति तय हो चुकी है ।

Crimes against Women

*761. SHRIMATI GEETA MUKHERJEE:

SHRI INDRAJIT GUPTA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether any survey of crimes against women has been made;

(b) whether statistics relating thereto have been compiled;

(c) if so, the findings thereof; and

(d) if not, whether Government propose to undertake such a survey?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) to (d). State-wise figures of incidents of crime against women *viz.*, (i) Reported cases of rape from 1975 to 1978. (ii) Wife burning tragedies from 1975 to 1979, (iii) Suicides by newly married women from 1977 to 1979 and iv) Cases of dowry deaths in 1978-79 are given in the enclosed statements. (Annexure I to IV).

To make a more comprehensive survey of crime against women, the Bureau of Police Research and Development has currently undertaken on the subject, a project for study, which is in progress.